



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 ई0 (आश्विन 10, 1943 शक सम्वत्) [संख्या-40

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	501-504	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	371-733	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	299	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

नियोजन अनुभाग-2

19 अगस्त, 2021 ई0

संख्या 55/XXVI/दो (20)/2004-

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- अर्थ एवं संख्या निदेशालय में अपर निदेशक के एक अतिरिक्त पद (अस्थाई) की निरन्तरता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2061/स्था0-1/2001-02, दिनांक 22.02.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निदेशालय के अन्तर्गत भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सौंपे गये कार्य यथा-सतत् विकास लक्ष्यों के अनुश्रवण एवं समन्वयन, सपोर्ट फार स्टैटिस्टिकल स्ट्रैथिंग प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन, आर्थिक सर्वेक्षण, मानव विकास रिपोर्ट, जी0आई0एस0 आधारित अनुश्रवण व्यवस्थापना आदि के कार्यों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए अर्थ एवं संख्या निदेशालय में अपर निदेशक वेतनमान 123100-215900 (लेवल-13) में एक अतिरिक्त अस्थायी पद शासनादेश संख्या-67/XXVI/दो(20)/2004, दिनांक 29.08.2019 द्वारा दिनांक 29.02.2020 तक के लिए सृजित किया गया था। उक्त वर्णित शासनादेश द्वारा सृजित अपर निदेशक के पद की अग्रेतर अवधि अर्थात् दिनांक 01.03.2021 से 28.02.2022 तक विस्तारीकरण किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-07 के अधीन लेखाशीर्षक -3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 112-आर्थिक सलाह और सांख्यिकी, -03-अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-296/XXVII(7)/2021 दिनांक 01.06.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-2

विज्ञप्ति

19 अगस्त, 2021 ई0

संख्या 670/2021-XIX-2/18 खाद्य/2010 टी0सी0-अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या-191(1)/2019-FCA/Ce दिनांक 18.05.2020 तथा निदेशक (एफसी लेखा डिबीजन), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र संख्या-191(1)/2019-FCA/Ce दिनांक 24.02.2020 के क्रम में गठित राज्य स्तरीय समिति (State Level Committee) द्वारा प्रस्तावित मण्डी लेबर चार्ज की दर दिनांक 01.04.2021 से आगामी 03 वर्षों के लिए निम्नवत् मदवार स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	मद	दर प्रति कुन्तल (₹ में)
1.	Unloading the Farmer's produce and heap wherever applicable	8.00
2.	Weighing	6.00
3.	Bagging	2.00
4.	Stiching & Labelling	4.00
5.	Loading for Dispatch from procurement Centre	6.00
	Total-	26.00

आज्ञा से,

भूपाल सिंह मनराल,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग-1विज्ञप्ति/पदोन्नति

19 अगस्त, 2021 ई0

संख्या 894/II(1)/2021-01(29)(18)/2011-15-सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) वेतनमान रू0 44900-142400 पे मैट्रिक्स-7 से सहायक अभियंता (सिविल) वेतनमान रू0 56,100-1,77,500 पे मैट्रिक्स-10 के रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या-97/18/ई-1(4)0/डी0पी0सी0/2020-21 दिनांक 15.07.2021 द्वारा नियमित चयनोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कनिष्ठ अभियंता (सिविल) को चयन वर्ष 2019-20 के चयन के सापेक्ष सहायक अभियंता (सिविल) वेतनमान रू0 56,100-1,77,500 लेवल-10 के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. श्री विजय कुमार अरोड़ा
2. श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डे
3. श्री जगत सिंह बिष्ट
4. श्री कुताली लाल

2. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा पदस्थापना सम्बन्धी आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या-151/SS/2010 श्री मनीष सेमवाल बनाम राज्य एवं रिट याचिका संख्या-265/SB/2018 श्री विनोद कुमार बनाम राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,
हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 ई0 (आश्विन 10, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

September 14, 2021

No. F-9(32)/RG/UERC/2021/534: In exercise of powers conferred under Section 61 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:

PART I

PRELIMINARY

1. Short Title, extent and Commencement

- (1) These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Multi Year Tariff) Regulations, 2021, in short, UERC Tariff Regulations, 2021.
- (2) These Regulations shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.
- (3) These Regulations shall be applicable for determination of tariff in all cases covered under these Regulations from FY 2022-23 onwards and upto FY 2024-25, i.e. from April 1, 2022 to March 31, 2025.

2. Scope of Regulations

(1) These Regulations shall apply in the following cases:-

a) Supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee:

Provided that the Commission may, in case of shortage of supply of electricity, fix the minimum and maximum ceiling of tariff for sale or purchase of electricity in pursuance of an agreement, entered into between a Generating Company and a Licensee or between Licensees, for a period not exceeding one year to ensure reasonable prices of electricity;

b) Intra-State transmission of electricity;

c) SLDC Charges;

d) Retail supply of electricity;

Provided that in case of distribution of electricity in the same area by two or more Distribution Licensees, the Commission may, for promoting competition among Distribution Licensees, fix only maximum ceiling of tariff for retail sale of electricity;

Provided further that where the Commission has permitted open access to any category of consumers under section 42 of the Act, the Commission shall determine the wheeling charges, cross-subsidy surcharge, additional surcharge and other open access related charges in accordance with these Regulations and the UERC Intra-State Open Access Regulations as amended from time to time.

(2) These Regulations shall not apply for determination of tariff in case of the following:

(a) Generating stations whose tariff has been discovered through a transparent process of bidding in accordance with the competitive bidding guidelines notified by the Central Government and adopted by the Commission under Section 63 of the Act.

(b) Generating stations of renewable sources of energy, which shall be governed by UERC RE Regulations as amended from time to time or any subsequent enactment thereof.

(3) For all purposes, including the review matters pertaining to the period till 31.03.2022, the issues related to determination of tariff shall be governed by the Regulations prevalent during that period.

3. Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires,

(1) "Accounting Statement" means for each financial year, the following statements, namely-

a) Balance sheet, prepared in accordance with the form contained in Part I of Schedule III to the Companies Act, 2013 as amended from time to time;

b) Cash flow statement, prepared in accordance with the Accounting Standard on Cash Flow Statement (AS-3) of the Institute of Chartered Accountants of India or Ind AS 7 issued by the Accounting Standard Board;

c) Cost records prescribed by the Central Government under Section 128(1) of the Companies Act, 2013;

- d) Together with notes thereto, and such other supporting statements and information as the Commission may direct from time to time;
- e) Profit and loss account, complying with the requirements contained in Part II of Schedule III to the Companies Act, 2013;
- f) Report of the statutory auditors';

Provided that in case of any local authority engaged in the business of distribution of electricity, the Accounting Statement shall mean the items, as mentioned above, prepared and maintained in accordance with the relevant Acts or Statutes as applicable to such local authority.

- (2) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto.
- (3) "Additional Capitalisation" means the capital expenditure actually incurred or projected to be incurred, after the date of commercial operation of the Project and admitted by the Commission after prudence check subject to provisions of Regulation 22.
- (4) "Aggregate Revenue Requirement" means the requirement of the Transmission Licensee or the Distribution Licensee or Generating Company or SLDC for recovery, through tariffs, of all the allowable expenses and return pertaining to its Licensed/Regulated Business for a particular financial year, in accordance with these Regulations;
- (5) "Allocation Statement" means for each financial year, a statement in respect of each of the separate businesses of the Licensees/Generating Company/SLDC, showing the amounts of any revenue, costs, assets, liabilities, reserves or provisions, which has been either;
 - a) Charged from or to each such separate business together with a description of the basis of that charge; or
 - b) Determined by apportionment or allocation between the Licensed/Regulated Business and every other separate business of the Licensee/Generating Company, together with a description of the basis of the apportionment or allocation;

Provided that such allocation statement in respect of a generating station shall be maintained in a manner so as to enable tariff determination, stage-wise, unit-wise or for the whole generating station.

- (6) "Applicant" means a Generating Company or a Transmission Licensee or a Distribution Licensee or SLDC who has made an application/Petition for determination of Aggregate Revenue Requirement and/or tariff or an application for Annual Performance Review in

accordance with the Act and these Regulations and includes a Generating Company or a Transmission Licensee or a Distribution Licensee or SLDC whose tariff is the subject of a review by the Commission either suo-moto or on a petition filed by any interested or affected person or as part of an Annual Performance Review;

(7) "Auditor" means an auditor appointed by the generating company or licensee or SLDC, as the case may be, in accordance with the provisions of Sections 224, 233B and 619 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)], as amended from time to time or Chapter X of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or any other law for the time being in force;

(8) "Auxiliary Energy Consumption" in relation to a period, in case of generating station means the quantum of energy consumed by auxiliary equipment of the generating station, such as the equipment used being used for the purpose of operating plant and machinery including switchyard of the generating station and transformation losses within the generating stations and shall be expressed as a percentage of the sum of gross energy generated at the generator terminals of all the units of the generating station;

Provided that the colony consumption and other facilities of a Generating Station and the power consumed for construction works at the Generating Station shall not be included as part of the Auxiliary Energy Consumption for the purpose of these Regulations.

Provided further that auxiliary energy consumption for compliance of revised emission standards, sewage treatment plant and external coal handling plant (jetty and associated infrastructure) shall be considered separately.

(9) "Availability" in relation to a transmission system for a given period means the time in hours during that period in which the transmission system is capable of transmitting electricity at its rated voltage to the delivery point and shall be expressed in percentage of total hours in the given period;

(10) "Base year" means the year which is two financial years preceding the first year of the Control Period and for the Control Period covered by these Regulations, the base year shall be FY 2020-21;

(11) "Beneficiary" in relation to a generating station means a person purchasing electricity generated at such generating station whose tariff is determined under these Regulations; and in relation to the transmission business means the person who has contracted the transmission capacity on payment of transmission charges.

(12) "Block" in relation to a combined cycle thermal generating station includes combustion

turbine - generators, associated waste heat recovery boilers, connected steam turbine - generators and auxiliaries;

- (13) "Capital Cost" means the Capital Cost as determined in accordance with Regulation 21;
- (14) "CERC" means the Central Electricity Regulatory Commission;
- (15) "Change in law" means occurrence of any of the following events having implication for the generating station or the transmission system or distribution system or SLDC's operations covered by these Regulations:
- a) Enactment, bringing into effect, adoption, promulgation, amendment, modification or repeal of any law; or
 - b) Change in interpretation or application of any Indian law by a competent court, Tribunal or Indian Governmental Instrumentality which is the final authority under law for such interpretation or application; or
 - c) Change by any competent statutory authority, in any condition or covenant of any consent or clearances or approval or licence available or obtained for the project; or
 - d) Coming into force or change in any bilateral or multilateral agreement/treaty between the Government of India and any other Sovereign Government.
- (16) "Commission" means the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission constituted under Section 82 of the Electricity Act, 2003;
- (17) "Control Period" means a period of three financial years from April 1, 2022 to March 31, 2025, for which the principles of determination of revenue requirement and tariff are specified in these Regulations;
- (18) "Conventional Power Plants" means gas based thermal, or hydro generating stations of capacity exceeding 25 MW.
- (19) "Cut-off Date" means 31st March of the year closing after two years of the year of commercial operation of whole or part of the project, and in case the whole or part of the project is declared under commercial operation in the last quarter of a year, the cut-off date shall be 31st March of the year closing after three years of the year of commercial operation;
- Provided that the cut-off date may be extended by the Commission if it is proved on the basis of documentary evidence that the capitalization could not be done within the cut-off date for reasons beyond the control of the project developer;

(20) "Date of commercial operation" or 'COD' of a generating station or unit or block thereof or a transmission system or element thereof shall be determined as under:

- a) Date of commercial operation in case of a generating unit or block of the thermal generating station shall mean the date declared by the generating company after demonstrating the maximum continuous rating (MCR) or the installed capacity (IC) through a successful trial run after notice to the beneficiaries, if any, and in case of the generating station as a whole, the date of commercial operation of the last generating unit or block of the generating station:
- b) Date of commercial operation in relation to a generating unit of hydro generating station shall mean the date declared by the generating company from 00:00 hour after the scheduling process in accordance with the Grid code, is fully implemented, and in relation to the generating station as a whole, the date declared by the generating company after demonstrating peaking capability corresponding to installed capacity of the generating station through a successful trial run:

Provided that:

- (i) Where the beneficiaries have been tied up for purchasing power from the generating station, the trial run shall commence after seven days notice by the generating company to the beneficiaries and scheduling shall commence from 0000 hr after completion of the trial run:
- (ii) The generating company shall certify to the effect that the generating station meets the key provisions of the technical standards of Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electrical plants and electric lines) Regulations, 2010 and Grid Code:
- (iii) In case a hydro generating station with pondage or storage is not able to demonstrate peaking capability corresponding to the installed capacity for the reasons of insufficient reservoir or pond level, the date of commercial operation of the last unit of the generating station shall be considered as the date of commercial operation of the generating station as a whole, and it will be mandatory for such hydro generating station to demonstrate peaking capability equivalent to installed capacity of the generating unit or the generating station as and when such reservoir/pond level is achieved:
- (iv) If a run-of-river hydro generating station or a generating unit thereof is declared

under commercial operation during lean inflows period when the water inflow is insufficient for such demonstration of peaking capability, it shall be mandatory for such hydro generating station or generating unit to demonstrate peaking capability equivalent to installed capacity as and when sufficient water inflow is available.

- (v) The certificate regarding commissioning of the generating station and compliance of all the Rules and Regulations in this regard and also of the CEA Technical Standards for Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulations, 2010, as amended from time to time, shall be signed by CMD/CEO/MD of the company subsequent to its approval by the Board of Directors in the format enclosed at **Appendix - V:**

- c) Date of commercial operation in relation to a transmission system shall mean the date declared by the transmission licensee from 00:00 hour of which an element of the transmission system is in regular service after successful trial operation for transmitting electricity at rated voltage:

Provided that:

- (i) Clearance from the Electrical Inspector as prescribed in the Rules would be required before charging any transmission line or substation.
- (ii) Where the transmission line or substation is dedicated for evacuation of power from a particular generating station, the generating company and transmission licensee shall endeavour to commission the generating station and the transmission system simultaneously as far as practicable and shall ensure the same through appropriate Transmission Service Agreement in accordance with Regulation 21(7) of these Regulations:
- (iii) In case a transmission system or an element thereof is prevented from regular service for reasons not attributable to the transmission licensee or its supplier or its contractors, the transmission licensee shall approach the Commission through an appropriate application for approval of the date of commercial operation of such transmission system or an element thereof. The Commission in such cases, may approve the date of commercial operation prior to the transmission system or an element coming into regular service.
- (iv) In case of a Distribution Licensee, date of commercial operation shall mean the

date of charging the electric line or sub-station of a Distribution Licensee to its rated voltage level or seven days after the date on which it is declared ready for charging by the Distribution Licensee, but is not able to be charged for reasons not attributable to its suppliers or contractors, whichever is earlier:

Provided that clearance from the Electrical Inspector as prescribed in the Rules would be required before charging any HT/EHT line or substation.

Provided that the date of commercial operation shall not be a date prior to the scheduled date of commercial operation mentioned in power purchase agreement or the implementation agreement or the transmission service agreement or wheeling agreement or the investment approval, as the case may be, unless mutually agreed to by all Parties,

- (21) "Day" means the 24 hour period starting at 0000 hour;
- (22) "Declared Capacity" or "DC" in relation to a generating station means, the capability to deliver ex-bus electricity in MW declared by such generating station in relation to any time-block of the day or whole of the day, duly taking into account the availability of fuel or water, and subject to further qualification included in the relevant Regulations;
- (23) "De-capitalization" for the purpose of the tariff under these regulations, means reduction in Gross Fixed Assets of the project corresponding to the removal/deletion of assets as admitted by the Commission;
- (24) "Design Energy" means the quantum of energy which can be generated in a 90% dependable year with 95% installed capacity of the hydro generating station;
- (25) "Deviation Settlement Charges" (DSM charges) means DSM charges as defined in UERC (Deviation Settlement Mechanism and Related matters) Regulations, 2017, as amended from time to time or any subsequent re-enactment thereof,
- (26) "Distribution Business" means the business of operating and maintaining a distribution system for supplying electricity in the area of the supply of the Distribution Licensee;
- (27) "Distribution loss" means the energy losses in the distribution system of a distribution licensee including auxiliary power consumption in the sub-station for the purpose of air-conditioning, lightning, battery charging, accessories of sub-station equipments etc;
- (28) "Element" in respect of a transmission system shall mean an asset which has been distinctively defined under the scope of the project in the Investment Approval;

चूंकि साप्ताहिक गजट के
खण्ड भाग-1-क में पेंज संख्या
अधिक होने के कारण पेंज संख्या
379 से 730 तक अपलोड नहीं हैं।

SLDC

Form: F - 11

Working Capital Requirement

(Figures in Rs Crore)

S.No.	Particulars	Previous Year (n-1) (Actuals/Audited)	Current Year (n)			Ensuing Year (n+1) Projected	Ensuing Year (n+2) Projected	Ensuing Year (n+3) Projected	Remarks
			Apr- Sep (Actual)	Oct-Mar (Estimated)	Total (April - March)				
1	O&M expenses (equivalent to 1 month)								
2	Maintenance Spare (15% of operation and maintenance expenses)								
3	Receivables (Two months of SLDC Charges)								
4	Total Working capital								
5	Interest Rate (State Bank Advance Rate (SBAR))								
6	Interest on Working capital								

Petitioner

SLDC

Form: F-12

LDCD Fund

Sr. No.	Particulars	Ensuing year (n+1)	Ensuing Year (n+2)	Ensuing Year (n+3)	Remarks
a	Opening LDCD Fund				
	Add:				
b	Additions in LDCD Fund during the year on account of:				
(i)	Short Term Open Access				
(ii)	Registration Fees				
(iii)					
(iv)					
c	Total LDCD Fund				
d	Less:				
d(i)	Utilisation for Capital Expenses				
d(ii)	Utilisation for Revenue Expenses				
e	Net LDCD Fund as on 31st March of the Year				
f	Average Fund accumulated during the Year				
	Total				

SLDC

Form: F - 13

Investment Plan for Next 3 Years

S. No.	Name of Scheme / Description of investment	Total Project Cost	Ensuing Year (n+1)	Ensuing Year (n+2)	Ensuing Year (n+3)
1	2	3	4	5	6
1	Enhancement of Real Time Data Acquisition Capability				
2	Establishment of Training & System Studies Facilities at LD Centre				
3	Development of Application Software for Operator Assistance				
4	Effective Communication System				
5	Energy Accounting Balancing & Settlement Mechanism.				
6	Infrastructural Development				
7	Any other Investment (Please Specify)				
	Total				

Petitioner

By Order of the Commission,

NEERAJ SATI,
Secretary,

Uttarakhand Electricity Regulatory Commission.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 40 हिन्दी गजट/410-भाग 1-क-2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 ई0 (आश्विन 10, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

The general public is informed that I have changed my name from ISLAMAT KHAN to SALAMAT KHAN and in future. I should be known as SALAMAT KHAN S/o Ishak Khan Address, Mohalla Ghosiyan, Jwalapur, Haridwar, Uttarakhand

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SALAMAT KHAN S/o Ishak Khan

Address, Mohalla Ghosiyan,

Jwalapur, Haridwar, Uttarakhand

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 40 हिन्दी गजट/410—भाग 8—2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।